सरकारी संपत्तियों में बढ़ेगा निजी निवेश

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना...बुनियादी ढांचा संपत्तियों में विदेशी निवेशकों को भी मिलेगा मुनाफा कमाने का मौका

नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के जरिये बुनियादी ढांचा योजनाओं पर खर्च के लिए पैसे जुटाने का चार साल का रोडमैप बनाया है। इस योजना से सरकारी बुनियादी ढांचा संपत्तियों में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। विदेशी निवेशकों को भी मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा।

फिक्की ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा पैनल के को-चेयरमैन शैलेश पाठक ने बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजना और बुनियादी ढांचा संपत्तियां अलग-अलग हैं। बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक ऐसी संपत्तियों में पैसे लगाने की मंशा रखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले 24 महीने में टोल ऑपरेट ट्रांसफर के जरिये 17,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके अलावा 5 हजार करोड़ रुपये बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट से भी मिला है। पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ने भी पिछले कुछ महीनों में करीब 7,700 करोड़ रुपये की पूंजी जुटा ली है। लिहाजा इसमें कोई संशय नहीं कि यह योजना निजी क्षेत्र से बड़ा निवेश खींचने में कामयाब होगी। सरकार ऐसी संपत्तियों को निजी क्षेत्र या विदेशी कंपनियों को सौंपेगी, जिनका सुचारू संचालन वह खुद नहीं कर पा रही है। ब्यूरो

1.5 लाख करोड़ रुपये हर साल जुटाए जा सकेंगे योजना के तहत

■ **2021-22 में 88 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य : नीति आयोग**

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि योजना में हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। 2021-22 में मुद्रीकरण के जरिये 88 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। योजना से जुटाई राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा क्षेत्र को मजबूत बनाने में होगा, जिससे हर साल लाखों रोजगार भी पैदा किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, चूंकि मुद्रीकरण की जिम्मेदारी हमें दी गई है। लिहाजा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस योजना में किसी भी संपत्ति को बेचा या उसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह अनुबंध के आधार पर काम करेगा और जनता तक संपत्तियों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाने का काम सरकार करेगी।

■ **दिल्ली में 240 एकड़ बनेंगी कॉलोनी-वाणिज्यिक संपत्तियां**

एनएमपी योजना के तहत दिल्ली के सरोजिनी नगर, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर और घटोरणी में 240 एकड़ भूमि पर आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयां जैसे होटल, दुकानें आदि विकसित किए जाएंगे। योजना में अन्य आवासीय कॉलोनियां व आईटीडीसी के आठ होटल भी शामिल हैं।

कहां-कितनी संपत्तियों की पहचान

सड़क

26,700 किलोमीटर के राजमार्ग और सड़कों को ठेके पर देने के लिए पहचान की जा चुकी है

दूरसंचार

2.86 लाख किलोमीटर के भारतनेट फाइबर के अलावा बीएसएनएल व एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टॉवर का भी मुद्रीकरण होगा

ऊर्जा 28,608 सर्किट किलोमीटर की बिजली आपूर्ति लाइन के अलावा 6 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन संपत्तियों को भी मुद्रीकरण योजना में शामिल किया गया है

गैस

8,154 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन व 3,930 अन्य पाइपलाइन

भंडारण

एफसीआई व सीडब्ल्यूसी के 755 लाख टन क्षमता वाले भंडार

रेलवे 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 741 किमी का कोंकण रेलमार्ग और 15 रेलवे स्टेडियम व कॉलोनियों को भी निजी क्षेत्र को दिया जाएगा

■ **खनन :** 160 कोयला खदानें मुद्रीकरण योजना में शामिल

■ **हवाईअड्डे :** 25 हवाईअड्डों से भी पैसे जुटाएंगे

■ **बंदरगाह :** 9 बड़े बंदरगाहों का भी मुद्रीकरण करेगी सरकार

■ **स्टेडियम :** दिल्ली, बंगलूरू सहित कई शहरों के बड़े स्टेडियम ठेके पर दिए जाएंगे